

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/117-85/32756.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सैक्टर 4, गुड़गांव के श्रमिक श्री भीम सिंह, पुत्र श्री बाल मुकुन्द मार्फत मर्कनटाईल इम्पलाईज एसोसिएशन, एच-347, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट मानना जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री भीम सिंह को सेवा समाप्ति/छंती न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/117-85/32763.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सैक्टर 4, गुड़गांव, के श्रमिक श्री बाबू सिंह, पुत्र श्री राम दत्त सिंह मार्फत मर्कनटाईल इम्पलाईज एसोसिएशन, एच-347, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060 तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे निर्दिष्ट मानना जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री बाबू सिंह की सेवा समाप्ति/छंती न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 20 अगस्त, 1987

सं० ओ० वि०/रोह/7-87/33225.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि डायरेक्टर प्रिंसिपल मैडीकल कालज, रोहतक के श्रमिक श्रीमती दर्शना देवी, रानी श्री जगदीश गांधी, मकान नं० 477/20, सर्कुलर रोड, डी. एंज. एफ. कालोनी, रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-अम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्रीमती दर्शना देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

सं० ओ० वि०/रोह/6-87/33232.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि डायरेक्टर प्रिंसिपल मैडिकल कालज, रोहतक, के श्रमिक श्री राम मेहर, पुत्र श्री कृष्ण, गांव व डा० भैनी सुरजन, तह० महम, जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-अम

18/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रदन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :-

क्या श्री राम मेहर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत का हकदार है ?

सं. प्रो.वि./रोहं/91-87/33239—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, जम्नीगढ़, (2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, रोहतक के श्रमिक श्री जय नारायण हैल्पर, पुत्र श्री गजे सिंह, गांव फरमाना पास, तह. मेहम. जिन्ना रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इससे बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-अम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रदन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :-

क्या श्री जय नारायण हैल्पर की सेवा समाप्ति/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, यह किस राहत का हकदार है ?

सं. प्रो.वि./अम्ब/70-87/33247.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) आयुक्त, अम्बाला, (2) नगरपालिका, अम्बाला शहर के श्रमिक श्री सरवन कुमार, पुत्र श्री राम स्वयं, प्लॉट नं. 65/213, परेड मैदान, तोपखाना बाजार, अम्बाला छावनी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इससे बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3 अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रदन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :-

क्या श्री सरवन कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत का हकदार है ?

सं. प्रो.वि./अम्ब/53-87/33254.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) उपायुक्त, अम्बाला, (2) नगरपालिका, झुण्डापुर (अम्बाला) के श्रमिक श्री बलवंत सिंह, पुत्र श्री सुन्दर सिंह, गांव ब. ज. गढ़ी कोटा, तह. नारायणगढ़, जि. अम्बाला तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इससे बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3 अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रदन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :-

क्या श्री बलवंत सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत का हकदार है ?